।। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।।

REGD No. MH/MR. SOUTH-46/2009-11 RNI No. 43892/87

JANMABHOOMI GROUP

वर्ष : २४, अंक : १८

आर्थिक और व्यापार विषयक साप्ताहिक

विमान सरचार्ज गुजरात राज्य में ५० पैसा,
भारत के अन्य स्थानों पर १ रुपया

http://www.janmabhoominewspapers.com

व्यापार

VYAPAR, MUMBAI | मुंबई, २६ जुलाई से १ अगस्त, २०१० | पृष्ठ संख्या : १० | मूल्य : रु. ४.००

यूनिफार्म में अच्छी मांग, महंगे काटन माल, सिंथेटिक साड़ियों में ग्राहकी नहीं...... पृष्ठ १०

विभक्त सरकार

इस्लामाबाद में हमारे विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने नाक कटा दी- अपनी और भारत की- अब पाकिस्तान के साथ बातचीत दरकिनार हो गई है । हमारी सरकार और मंत्रियों में वाद-विवाद बढ़ गया है! यूनाइटेड सरकार फिलहाल 'शंभूमेला' जैसी प्रतीत होती है- मंत्री मनमाना व्यवहार करते और बोलते हैं। किसी विषय में एकवाक्यता और एकसूत्रता नहीं है । विदेश मंत्री वि. गृहमंत्री वि. रेलवे मंत्री वि. कांग्रेस प्रवक्ता... और ऐसी परिस्थिति में गृह सचिव पिल्लै को यह सुझाव दिया जाए कि आपको मीड़िया के समक्ष बोलना नहीं है- यह कितनी शर्मनाक बात है ! कांग्रेस के सचिवों और प्रवक्ताओं पर भी 'सेंसरशिप' का नियम लगाया गया है।

एक तरफ पाकिस्तान के साथ संबंध एवं बातचीत का विवाद है तो दूसरी तरफ बिहार और बंगाल का चुनाव आ रहा है, इसलिए नौटंकी प्रारंभ हो गई है । इस चुनाव में सेक्युलरवाद को केन्द्र में रखने के लिए गुजरात में सोहराबुद्दीन एन्काउंटर और गृहमंत्री अमित शाह को हाजिर किया गया है । विपक्षी एकता न बने और भाजपा से अन्य पार्टियां दूर भागें ऐसी गणित है अब देखना है कि यह सच होता है या नहीं।

दीवाने खास
-कुन्दन व्यास

इस्लामाबाद में हमारे विदेश मंत्री कृष्णा का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा यह हकीकत है, लेकिन विदेश मंत्रालय की विफलता गृह मंत्रालय पर थोपने का खेल शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच फिलहाल आतंकवाद और मुंबई पर हमले के मुद्दे पर चर्चा करनी है, लेकिन पाकिस्तान की चालबाजी कश्मीर को ही बीच में रखने की थी और वह सफल हो गई है । एक तो बातचीत का समय गलत था । पाकिस्तान ने कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू कराई थी । दूसरा-गृहसचिव पिल्लै ने पत्रकारों को जानकारी दी कि अमेरिका की जेल में हेडली ने कबूल किया कि आईएसआई द्वारा इशरत जहां (गुजरात में एंकाउंटर हुआ और फिर राजनीतिक विवाद छिड़ा) की भर्ती की गई थी। मुंबई पर हमला करने के लिए बोट खरीदने को २६ लाख रु. दिया गया और लगातार तालीम तथा मार्गदर्शन किया गया था- पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरेशी ने पिल्लै के वक्तव्य के खिलाफ आपत्ति जताई और उनकी जेहादी हाफिज सैयद के साथ तुलना की- तब भी हमारे कृष्णा मौन रहे- विरोध नहीं किया ।

भारत वापस लौटकर कृष्णा ने पिल्लै को दोषी करार किया और आखिरकार गृहसचिव पर 'सेंसरशिप' लगी । प्रश्न यह है

(शेष पृष्ठ २ पर)

जीएसटी : समान कर व्यवस्था का सपना साकार होगा ?

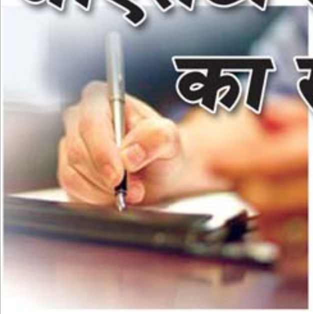

अप्रत्यक्ष करों में ऐतिहासिक सुधार पर मतभेद कायम

प्रवीण राणा

नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पहली अप्रैल १०११ से लागू करने के लिए अगले सप्ताह शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधेयक पेश करने जा रही है। इससे लगता है कि अप्रत्यक्ष करों में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कुछ प्रगति हुई है लेकिन देश में समान कर व्यवस्था का सपना साकार होगा, इसमें अभी भी संदेह है। विधेयक पेश होने से पूर्व कर की दरें घोषित की गई हैं लेकिन कई मुद्दों पर अब भी मतभेद कायम है जिस वजह से गुड्स एवं सेवाओं पर समान कर व्यवस्था- सिंगल रेट स्ट्रक्चर नहीं अपनाया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि फिलहाल समान कर व्यवस्था का सिंगल रेट स्ट्रक्चर संभव नहीं है। यह चरणवद्ध ढंग से संभव हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने तीन वर्ष के लिए जीएसटी के ढांचे की तीन दरें घोषित की (शेष पृष्ठ ८ पर)

राष्ट्रीय फाइबर नीति कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार

उद्योग से जुड़े संगठनों के सुझावों पर अंतिम चर्चा पूरी

प्रवीण राणा

नई दिल्ली । कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय फाईबर नीति तैयार कर दी है और अब इसे शीघ्र ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उद्योग से जुड़े संगठनों के सुझावों पर मंत्रालय ने अंतिम चर्चा पूरी कर दी है। मंत्रालय ने जो मसौदा तैयार किया था, उस पर कपड़ा उद्योग के सभी सेगमेंट ने अपने सुझाव दिए थे, कपड़ा मंत्रालय ने २० जुलाई को सभी संगठनों के साथ बैठक कर इस पर अंतिम चर्चा पूरी कर ली है।

इस नीति का मकसद देश में फाईबर की उपलब्धता बढाकर कपड़ा उद्योग का तीव्र विकास कर इसे प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस नीति के तहत देश में फाईबर की गुणवत्ता में सुधार करना है तथा कृत्रिम तथा सूती धागे पर लगे करों की असमानता को दूर करना भी है।

फाईबर नीति में कराधान के लिहाज से मानवनिर्मित कृत्रिम फाईबर तथा प्राकृतिक फाइबर सूती धागे में भेदभाव पर चिंता

(शेष पृष्ठ २ पर)

एमसीएक्स-एसएक्स की अदालत में याचिका

सेबी से इक्विटी और अन्य विभागों में कामकाज की मांगी मंजूरी

मुंबई। एसीएक्स-एसएक्स अनधिकृत होना कह कर सेबी इक्विटी मंच के अतिरिक्त इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, एफ एण्ड ओ म्यु. फंड और एसएमई सेगमेंट में कामकाज करने देने के लिए, नियामक सेबी को आदेश देने के लिए अदालत से न्याय की दरखास्त की है।

जिग्नेश शाह

मुंबई हाई कोर्ट में १६ जुलाई को दायर रिट याचिका में एमसीएक्स-एसएक्स ने हाईकोर्ट में अदालत के समक्ष आवेदन किया है कि इन विभागों में कामकाज भविष्य में उसे रोके नहीं। उसके लिए सेबी को आदेश दिया जाए ।

सेबी ने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कामकाज करने के लिए उसे अनुमति नहीं दी होने से उसकी विनिवेश की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है ।

सूत्रों ने कहा कि एमसीएक्स-एसएक्स ने सेबी के विरुद्ध १६ जुलाई को रिट याचिका दायर की और (शेष पृष्ठ २ पर)

Advt.